मानसून के तेवर से सकते में सरकार

- खरीफ सीजन के लिए धान और सोयाबीन का रकबा घटाया
- बोवनी के लिए जो टारगेट रखा, वह भी पूरा होना मुश्किल

कन्हैया लोधी

भोपाल, 16 जुलाई. मानसून के तेवर ने मप्र सरकार को सकते में ला दिया है. वैसे तो राज्य सरकार पहले ही मानसून की बेरूखी के अंदेशे से सतर्क हो गई थी. जिसके चलते खरीफ सीजन की दो मुख्य फसलें धान और सोयाबीन का रकबा पहले ही कम कर दिया गया है. लेकिन अब सरकार की दूसरी बड़ी चिंता यह है कि इन दोनों ही फसलों की बोनी के लिए जो टारगेट रखा है, वह पानी की कमी के चलते पूरी होती नजर नहीं आ रही है. ऐसे में अब सरकार कंटीजेंसी प्लान की तैयारी में लग गई है.

वैसे तो किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने मौजूदा खरीफ सीजन के लिए 150.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी का लक्ष्य रखा है जो कि पिछले सीजन के मुकाबले 5.62 लाख हेक्टेयर अधिक है. यह भी पहली बार हुआ है कि प्रदेश में खरीफ सीजन में बोवनी के कुल क्षेत्रफल का आंकड़ा डेढ़ करोड़ हेक्टेयर को पार कर गया है, लेकिन अब कृषि विभाग के अफसरों के मुताबिक बोवनी के इस लक्ष्य को हासिल करना अब आसान नहीं होगा.

भले ही आंकड़ों में कुछ भी दर्ज कर लिया जाए, जिस तरह खरीफ सीजन में मानसून की बेरूखी बनी हुई है, उससे प्रदेश के कमोबेश सभी क्षेत्रों में बोवनी प्रभावित हो रही है. अधिकारियों के मुताबिक यदि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फिर आकस्मिक योजना को अमल में लाने की तैयारी की जा सकती है. ऐसे में किसानों को ऐसी फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो कि कम अवधि में तैयार हो जाती है और उनको पानी की जरुरत भी कम पड़ती है. सरकार मानसून की बेरुखी की स्थिति में सभी विकल्पों के लिए तैयार है.

सोयाबीन की 6 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में बोनी

प्रदेश में खरीफ सीजन में सबसे अधिक क्षेत्र में ली जाने वाली फसल सोयाबीन है. प्रदेश में सोयाबीन का नार्मल एरिया 60.18 लाख हेक्टेयर है. लेकिन सरकार ने इस बार बोवनी का रकबा घटाकर 54.09 लाख हेक्टेयर कर दिया है जो कि पिछले वर्ष के 54.70 लाख हेक्टेयर से भी कम है. लेकिन अब तक लगभग 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बोवनी की जा सकी है. सबसे बड़ी बात ये कि जहां ये फसल लगी है, वहीं अब पानी की किल्लत भी होने लगी है, जिससे आने वाले दिनों में बोवनी के साथ ही उत्पादन भी प्रभावित होने का अंदेशा बन गया है.

75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही अब तक हुई बोवनी

खरीफ सीजन में बोवनी का सीजन लगातार निकल रहा है, अब तक प्रदेश में महज 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बोवनी किया जा सका है. यानी अभी लगभग आधा सफर ही तय हुआ है. पिछले वर्ष प्रदेश में 144.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी की गई थी, वहीं खरीफ के लिए सामान्य रकबा 145.98 लाख हेक्टेयर है. इस बार राज्य सरकार ने दलहन और तिलहन दोनों ही फसलों की बोवनी का रकबा बढ़ा दिया है. दलहन का रकबा 5.28 लाख से बढ़ाकर 8.27 लाख हेक्टेयर किया गया है, वहीं तिलहन बोवनी का रकबा 60.82 लाख से बढ़ाकर 63.06 लाख हेक्टेयर किया गया है.

धान का एरिया ढाई लाख हेक्टेयर घटाया

मौसम विभाग ने पहले ही कमजोर मानसून का अंदेशा जता दिया था, लिहाजा राज्य सरकार ने इस बार पहले ही धान और सोयाबीन बोवनी का लक्ष्य घटा दिया है. ये दोनों ही फसलें खरीफ सीजन की सबसे मुख्य फसल है. लेकिन इस बार धान की बोनी का लक्ष्य 2.47 लाख हेक्टेयर तक घटा दिया गया है. पिछले वर्ष प्रदेश में 42.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी की गई थी, लेकिन इस बार महज 39.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बोवनी का टारगेट रखा गया है. लेकिन अब तक की अवधि में बमुश्किल 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बोनी की जा सकी है, जो कि पिछले सीजन के मुकाबले आधा भी नहीं है. गुजरते वक्त के साथ देर तक पकने वाली किस्मों के रोपण के लिए समय भी निकल रहा है.

महाकाल सवारी बनी सिंहस्थ की तैयारियों का निर्णायक आधार

चौड़ीकरण के कार्य ने पकड़ी रफ्तार

परंपरागत मार्ग हर हाल में होगा तैयार

रात में निर्माण कार्य से मिली सफलता

नवभारत न्यूज

उज्जैन. यदि इस समय सावन पर्व नहीं आता या बाबा महाकाल की सवारी का दौर नहीं होता तो संभवत: शहर के चौड़ीकरण और सड़क निर्माण कार्यों की रफ्तार पहले जैसी ही धीमी बनी रहती. अब जिस तरह 3 अगस्त को सावन की पहली सवारी परंपरागत मार्ग से निकले, और वर्षों पुराने रीती रिवाजों में कोई बदलाव न हो, मार्ग परिवर्तित न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत झोंक दी है. यही कारण है कि लंबे समय से सुस्त गति से चल रहे चौड़ीकरण कार्य अब दिन के साथ रात में भी युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं.

दरअसल, सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत शहर के प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण और विकास कार्य चल रहा है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण वही मार्ग है, जहां से बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलती है. सावन की सवारी नजदीक आते ही प्रशासन की प्राथमिकता बदल गई है और अब पूरे फोकस के साथ निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है.

रात्रिकालीन कार्यों से जगी उम्मीद

इसी कड़ी में निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा प्रतिदिन देर रात स्वयं सवारी मार्ग पर पहुंच रहे है, कंठाल चौराहा, छत्री चौक और कमरी मार्ग, रामघाट, हरसिद्धि की पाल, गणगौर का दरवाजा तक पहुंच रहे है, तथा निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी. उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण, प्रीकास्ट नालियां, पेयजल पाइपलाइन शिफ्टिंग, विद्युत पोल स्थानांतरण, मंदिरों के विस्थापन, छज्जों के निराकरण, डीएलसी-पीक्यूसी सड़क निर्माण और चौराहों के विकास सहित सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरे किए जाएं. इसके लिए दिन और रात्रि दोनों शिफ्टों में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.

पूरा मार्ग 80% तैयार-प्रशासन की कोशिश है कि परंपरागत मार्ग पूरी तरह तैयार रहे, ताकि बाबा महाकाल की शाही सवारी हर वर्ष की तरह उसी ऐतिहासिक मार्ग से निकले और सदियों पुरानी परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे. यही कारण है कि रात में भी अधिकारियों की निगरानी बढ़ा दी गई है और निर्माण एजेंसियों की कार्य क्षमता भी बढ़ाई गई है. सवारी मार्ग 80% तैयार हो चुका है.

श्रद्धालुओं को सुगमता

महापौर मुकेश टटवाल ने भी निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सिंहस्थ और बाबा महाकाल की शाही सवारी, दोनों की दृष्टि से यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है. सभी निर्माण कार्य स्थायी गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे हों, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके.

धार्मिक परंपरा बनी रहे-प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि महाकाल की शाही सवारी केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि शहर के विकास कार्यों की गति तय करने वाला सबसे बड़ा अवसर भी बन गई है. सवारी की समय-सीमा ने वर्षों से लंबित चौड़ीकरण कार्यों में नई ऊर्जा भर दी है. अब लक्ष्य सिर्फ निर्माण पूरा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि 3 अगस्त को बाबा महाकाल की पहली सवारी बिना किसी व्यवधान के अपनी परंपरागत राह से निकले और उज्जैन की धार्मिक परंपरा की गरिमा बनी रहे.

मुख्यमंत्री का फैसला जमीन पर दिखे : पटवारी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा पशुपालन एवं गौ-संवर्धन विभाग अपने पास रखने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि असली परीक्षा विभाग अपने पास रखने की नहीं, बल्कि इससे प्रदेश में पशुपालन और गौ-कल्याण व्यवस्था में ठोस सुधार लाने की है.

उन्होंने कहा कि विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि यह निर्णय केवल प्रतीकात्मक साबित होगा या इससे जमीनी स्तर पर

बदलाव भी दिखाई देगा. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वर्षों से गौ-सुरक्षा को राजनीतिक प्राथमिकता बताती रही है, लेकिन प्रदेश में गौवंश की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है. गौशालाओं में चारा, पानी, दवाइयों और अन्य आवश्यक संसाधनों की कमी बनी हुई है.

जीतू पटवारी ने विधानसभा में सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में आवारा मवेशियों से जुड़े 237 सड़क हादसे हुए, जिनमें 94 लोगों की मृत्यु और 133 लोग घायल हुए. उनका आरोप है कि गौशालाओं को मिलने वाली सरकारी सहायता भी प्रति पशु प्रतिदिन होने वाले वास्तविक खर्च, जो लगभग 70 रुपये बताया जाता है, से काफी कम है. उन्होंने मुख्यमंत्री से पशुपालकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करने, गौशालाओं को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की.

तीन दिनों में साइबर ठगी के 10 मामले

ग्वालियर. शहर में साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. पुलिस के अनुसार पिछले तीन दिनों में साइबर ठगी के 10 मामले सामने आए हैं. इनमें पड़ाव, मुरार और महाराजपुरा थाना क्षेत्रों के तीन मामलों में पीड़ितों से कुल 2.82 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई है.

पुलिस के अनुसार पड़ाव थाना क्षेत्र की लक्ष्मीबाई कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय ललित स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें अप्रैल में टेलीग्राम के एक समूह में जोड़ा गया था. प्रारंभ में ऑनलाइन कार्य के बदले कुछ राशि देकर विश्वास हासिल किया गया.

पुराने पुल से नदी में गिरी एम्बुलेंस, चालक समेत दो घायल

मैहर, 16 जुलाई. मध्यप्रदेश के मैहर जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक एम्बुलेंस पुराने पुल से नीचे नदी में गिर गई. हादसे में चालक समेत दो लोग घायल हो गए. पुलिस सूत्रों के अनुसार एम्बुलेंस किसी मरीज को लेने जा रही थी. इसी दौरान बरुआ नदी के पुराने पुल से वाहन अनियंत्रित होकर नीचे नदी में जा गिरा. वही नदी में पानी कम होने के कारण चालक शुभम परौहा और एम्बुलेंस में सवार एक अन्य व्यक्ति की जान बच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाला. घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सत्र के पहले कांग्रेस की बैठक रविवार को

विशेष संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई . विधानसभा के सोमवार से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र को लेकर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक रविवार 19 जुलाई की शाम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के शासकीय निवास पर भोपाल में आयोजित होगी. बैठक में विधानसभा सत्र के लिए कांग्रेस की रणनीति तय की जाएगी तथा सरकार को विभिन्न जनहित के मुद्दों पर घेरने की रूपरेखा तैयार की जाएगी.

बैठक में कांग्रेस विधायक राज्य के प्रमुख जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह तय करेंगे कि

विधानसभा में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा. पार्टी रोजगार सृजन, भर्ती परीक्षाओं में सुधार, समान नागरिक संहिता (यूसीसी), अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अधिकार, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगेगी. इसके साथ ही प्रदेश में सामने आए कथित घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को भी विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाने की तैयारी की जाएगी. कांग्रेस इन मामलों में सरकार से विस्तृत जवाब और जवाबदेही सुनिश्चित करने की रणनीति बनाएगी. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल जनता की आवाज को पूरी मजबूती से विधानसभा में उठाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, केन-बेतवा परियोजना तथा आदिवासी और दलित समुदायों के अधिकार जैसे मुद्दे गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं और इन पर सरकार को जवाब देना होगा.

12 वर्षीय साली की हत्या के आरोप में जीजा गिरफ्तार

धार, 16 जुलाई. जिले की बाग थाना पुलिस ने 12 वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में फरार चल रहे उसके जीजा को महाराष्ट्र के शाहदा से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने पारिवारिक विवाद के चलते कथित रूप से बालिका की हत्या की थी. पुलिस के अनुसार 12 जुलाई को ग्राम रिसावला से 12 वर्षीय बालिका के लापता होने की सूचना पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान बालिका का शव पाडलिया घाटी के समीप वन विभाग के एक सीमेंटेड कुएं से बरामद हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया. जांच में पुलिस ने 24 वर्षीय अनिल दोहदिया निवासी सेवरिया, जोबट को आरोपी के रूप में चिन्हित किया. पुलिस के अनुसार आरोपी ने फरवरी 2026 में इंस्टाग्राम के माध्यम से परिचय होने के बाद मृतका की बड़ी बहन से विवाह किया था. हाल में पत्नी के मायके चले जाने और वापस आने से इनकार करने के बाद उत्पन्न पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने कथित रूप से बदला लेने की नीयत से बालिका को जंगल में ले जाकर कुएं में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई.

मध्यप्रदेश में मानसून की रफ्तार हुई धीमी

35 जिलों में बारिश की कमी

19 से तेज वर्षा के आसार

कम बारिश से उमस बढ़ी और लोग हुए परेशान

भोपाल, 16 जुलाई. मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार पिछले एक सप्ताह से धीमी बनी हुई है. लगातार सात दिनों से कहीं भी भारी या अति भारी बारिश नहीं होने के कारण प्रदेश में वर्षा का आंकड़ा सामान्य से पीछे चल रहा है. अब तक प्रदेश में 241.8 मिमी (करीब 9.5 इंच) बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस समय तक औसतन 270.3 मिमी (करीब 10.6 इंच) वर्षा होनी चाहिए थी. वहीं कम बारिश के कारण उमस से लोग परेशान हो रहे.

प्रदेश फिलहाल सामान्य से 11 प्रतिशत कम बारिश के दौर से गुजर रहा है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 जुलाई से नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने के बाद बारिश फिर जोर पकड़ सकती है.

बारिश की सबसे अधिक कमी पूर्वी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है. जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग सहित 35 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वी हिस्से में औसतन 24 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से 2 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है. लगातार कम बारिश से खरीफ फसलों, जलाशयों और भूजल स्तर पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मध्य प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है. यदि मौसम प्रणालियां अनुकूल रहीं तो जुलाई के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. गुरुवार को इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, और अनूपपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवा चलने के आसार हैं.

2.19 करोड़ रुपए की संपत्ति की राजसात

15 साल पुराने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में विशेष कोर्ट का फैसला

> विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाटीदार ने सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि मूल अपराध में आरोपी अंतिम रूप से दोषमुक्त हो जाता है तो उसके खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि मूल मामले में दोषमुक्ति के फैसले के खिलाफ राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट में कोई अपील दायर होने का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जारी रखने का आधार नहीं बचता और दोनों आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है.

नव भारत न्यूज

इंदौर. करीब 15 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने आरोपी दंपती को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन ईडी द्वारा अटैच की गई करीब 2.19 करोड़ रुपए की संपत्ति पर किसी ने दावा नहीं किया. ऐसे में अदालत ने पूरी संपत्ति शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिए हैं.

वर्ष 2011 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महू स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन क्लर्क राजेश नीम और अंजना नीम के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था. इससे पहले राजेश नीम के खिलाफ धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट के तहत पुलिस प्रकरण दर्ज हुआ था. इसी मूल अपराध को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. मूल आपराधिक मामले में फरवरी 2023 में दोनों आरोपियों को अदालत से दोषमुक्त कर दिया था.

इसके बाद उन्होंने विशेष पीएमएलए कोर्ट में आवेदन देकर मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण से भी बरी किए जाने की मांग की.

बैंक खाते, प्लॉट और संपत्तियां भी हुई राजसात...

जांच के दौरान ईडी ने बैंक खातों के साथ इंदौर के इंद्रपुरी स्थित संपत्ति और महू के एक प्लॉट समेत करीब 2.19 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अटैच की थी.

सुनवाई के दौरान आरोपियों ने इन बैंक खातों और अटैच संपत्तियों पर अपना कोई दावा पेश नहीं किया तथा कहा कि यह उनकी संपत्ति नहीं है. इसके बाद विशेष कोर्ट ने 14 जुलाई को आदेश जारी कर पूरी अटैच संपत्ति को शासन के पक्ष में राजसात करने के निर्देश दिए.

राशन घोटाला करने वाले प्रबंधक व विक्रेता को जेल

बड़वानी. गरीबों के हक के राशन में कथित गड़बड़ी करने वाले उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक व विक्रेता को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. बहुचर्चित राशन वितरण अनियमितता प्रकरण में न्यायालय ने पाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के वितरण एवं स्टॉक में गंभीर अनियमितताएं हुई थी. जांच के दौरान दुकान के पीओएस रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक के सत्यापन में गेहूं एवं चावल की बड़ी मात्रा कम पाई गई थी. शिकायतों और जांच के बाद प्रबंधक लालसिंह चौहान तथा विक्रेता राजू अलावे के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं आपराधिक न्यास भंग के आरोपों में प्रकरण दर्ज किया था. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने तकनीकी, दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए.

उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर 51 का वेतन कटा

सीधी. स्वास्थ्य विभाग में समयबद्ध उपस्थिति, कार्य संस्कृति में अनुशासन तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने सार्थक एप में नियमित उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले 51 कर्मचारियों के वेतन कटौती की कार्रवाई की है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से दर्ज की जाती है, जिससे उनकी उपस्थिति एवं कार्यस्थल पर उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाती है. समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 51 कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सार्थक एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित कर्मचारियों के वेतन में नियमानुसार कटौती की गई है.

नशामुक्ति अभियान बना जन आंदोलन

विशेष संवाददाता

भोपाल. मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' ने पहले ही दिन व्यापक जनसहभागिता दर्ज की. प्रदेशभर में आयोजित 600 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 1.85 लाख लोगों तक अभियान का संदेश पहुंचाया गया.

अभियान के तहत विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस कर्मियों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने रैलियों, मैराथन, जागरूकता दौड़, नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी, हस्ताक्षर अभियान, शपथ ग्रहण कार्यक्रमों तथा जनसंवाद में उत्साहपूर्वक भाग

लिया. इंदौर में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के बीच नशामुक्ति का संदेश देने वाला रोबोट कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा. बुरहानपुर में करीब 7,000 लोगों ने मैराथन में भाग लेकर नशे से दूर रहने की शपथ ली, जबकि झाबुआ में आयोजित नशामुक्ति दौड़ में लगभग 5,000 प्रतिभागी शामिल हुए. टीकमगढ़ और विदिशा में जागरूकता रथ, ध्यान सत्र और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए गए, वहीं सीहोर में सोशल मीडिया अभियान के साथ गांव-गांव जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की गईं. उज्जैन, धार, खरगोन, आगर-मालवा, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, छिंदवाड़ा सहित अनेक जिलों में भी विविध कार्यक्रम आयोजित हुए.

प्रयास | पारिवारिक, संपत्ति और भरण-पोषण संबंधी विवादों के समाधान का प्रभावी मंच

वरिष्ठ नागरिक पुलिस पंचायत ने सुलझाए विवाद

विशेष संवाददाता

भोपाल, 16 जुलाई. मध्यप्रदेश पुलिस की 'देशभक्ति-जनसेवा' की भावना के अनुरूप विदिशा पुलिस द्वारा संचालित सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत वरिष्ठ नागरिकों के पारिवारिक, संपत्ति और भरण-पोषण संबंधी विवादों के समाधान का प्रभावी मंच बनकर उभरी है. इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को समय पर न्याय, सम्मानजनक जीवन और भावनात्मक सुरक्षा उपलब्ध कराना है.

विदिशा पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन तथा

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में आयोजित हालिया पुलिस पंचायत में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े आठ प्रकरणों की सुनवाई की गई. कोर कमेटी ने सभी मामलों में संवाद, समझाइश और आपसी सहमति के माध्यम से समाधान कराने का प्रयास किया.

सबसे संवेदनशील मामले में एक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी की विधवा ने आरोप लगाया कि पति की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, जिससे अंतिम संस्कार के लिए भी उन्हें लोगों से आर्थिक सहायता मांगनी पड़ी. पुलिस की मध्यस्थता के बाद दोनों बेटों ने मां को किसी प्रकार से प्रताड़ित या घर से बेदखल नहीं करने तथा उन्हें पारिवारिक मकान में सम्मानपूर्वक रहने देने और संपत्ति संबंधी भविष्य के निर्णय का अधिकार स्वीकार किया.

शमशाबाद के एक मामले में पुत्र और बहू पर मारपीट के आरोपों का समाधान संपत्ति के मूल्यांकन और उचित मुआवजे पर सहमति के साथ हुआ. कुरवाई में भूमि विवाद के बाद चारों पुत्र अपने पिता के भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह दो-दो हजार रुपये देने पर राजी हुए.

इलेक्टिव कोर्स के बिना मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे छात्र

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 16 जुलाई. प्रदेश के सभी आयुर्वेद कॉलेजों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि बीएएमएस आयुर्वेद स्नातक के 2021-22 बैच के छात्र 9 इलेक्टिव कोर्स क्वालीफाई किये बिना मुख्य यूनिवर्सिटी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। बता दें बीएएमएस की कुल साढ़े 5 साल की डिग्री में 3 प्राफ (हर डेढ़ साल में होने वाली परीक्षा) होती है. जो कि प्रत्येक डेढ़ साल में होती है. जिसमें सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षाओं के अलावा आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न ऑनलाइन इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत प्रति प्रॉफ 3-3 परीक्षाओं में यानी कुल 9 इलेक्टिव कोर्स में पास होना अनिवार्य है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60